

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या 200/2015/बांसवाडा

रामलाल पुत्र वेगाजी जाति भील निवासी-ग्राम बारी डायलाब तहसील व जिला बांसवाडा। ...प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप-पंजीयक बांसवाडा जिला बांसवाडा।
2. श्रीमती कमली पत्नि गौतम जाति भील निवासी-ग्राम संग्रामपुरा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडाअप्रार्थीगण

एकलपीठ

श्री नत्थूराम -सदस्य

उपस्थित:

श्री रोहीत सोनी,
अभिभाषक
श्री जमील जई
उप राजकीय अभिभाषक

.....प्रार्थी की ओर से

.....अप्रार्थीगण 01 की ओर से

निर्णय दिनांक : 09.01.2017

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक), उदयपुर (जिसे आगे 'कलक्टर मुद्रांक' कहा गया है) के आदेश दिनांक 24.02.2012 प्रकरण संख्या 30/2008 के विरुद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे 'मुद्रांक अधिनियम' कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जिसमें कलक्टर (मुद्रांक) उदयपुर ने उप-पंजीयक द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया है।
2. प्रकरण में दस्तावेज बाद पंजीयन दिनांक 14.12.07 प्रार्थी को लौटा दिया था। अधीनस्थ न्यायालय में इस आधार पर रेफरेन्स प्रस्तुत हुआ कि क्रय की गई भूमि मुख्य सड़क पर तथा सड़क से 200 मीटर की सीमा में स्थित है तथा तदनुसार मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपने निगरानीधीन निर्णय दिनांक 24.02.12 द्वारा रेफरेन्स स्वीकार करते हुए कमी मुद्रांक कर 1,92,180/- रु. व शास्ति 320/- रु कुल 1,92,500/- रु. वसूल किये जाने के आदेश दिये हैं जिसके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।
3. निगरानी दर्ज की गई। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड एवं अप्रार्थी संख्या 02 की तलबी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है परन्तु प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए इसी स्तर पर निस्तारण हेतु बहस प्रार्थी व विद्वान उपराजकीय अभिभाषक की सुनी गई।
4. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हें विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है। निर्णय में रेफरेन्स के बिन्दुओं को बिना कोई विवेचना एवं विश्लेषण किये पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं है। निर्णय साइक्लोस्टाइल है व रिक्त स्थानों में पूर्ति कर निर्णय पारित कर दिया है। निर्णय में तर्क, कारण एवं विधिक विवेचना का अभाव है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है। इन्होंने यह भी कथन किया कि रेफरेन्स में मुख्य बिन्दु क्रय की गई

2m

लगातार.....2

कृषि भूमि सडक पर स्थित होने एवं सडक से 200 मीटर की सीमा में स्थित होने का बिन्दु निहित था जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की उपस्थिति में मौका देखकर ही निर्णित किये जाने योग्य था जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने तो मौका देखा है व न ही इस बिन्दु पर कोई निष्कर्ष दिया है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त किये जावे। इन्होंने अपने समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ के सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टैक्स,कोटा बनाम मैसर्स शुक्ला एड ब्रदर्स (Civil Appeal No. Nil of 2010/S.L.P.(C)No. 16466 of 2009), date 15.4.2010) में पारित किय गये निर्णय का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

5. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत हैं। अतः निगरानी खारिज की जावें।
6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-
7. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ होने, धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कारण कि उन्हें निर्णय की जानकारी वसूली नोटिस आने पर हुई, विश्वास योग्य होने के कारण एवं निर्णय गुणावगुण के आधार पर श्रेयस्कर होने की दृष्टिगत स्वीकार किया जाकर निगरानियां अन्दर मियाद मानी जाती है।
8. निगरानी में मुख्य आधार यह है कि निर्णय में रेफरेन्स के बिन्दुओं को बिना कोई विवेचना एवं विश्लेषण किये पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं है। निर्णय साइक्लोस्टाइल है व रिक्त स्थानों में पूर्ति कर निर्णय पारित कर दिया है। निर्णय में तर्क, कारण एवं विधिक विवेचना का अभाव है।

कलक्टर (मुद्रांक) उदयपुर के निगरानीधीन आदेशों के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि कलक्टर (मुद्रांक) ने निगरानी के तथ्यों का विवेचन किये बिना ही साइक्लोस्टाइल पेपर पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करके विवादित आदेश पारित किया है, जिसे न्याय संगत आदेश नहीं कहा जा सकता है। अपीलीय अधिकारी का दायित्व बनता है कि उसके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में उठाये गये बिन्दुओं की विवेचना करने के उपरान्त ही उन्हें मानने या न मानने पर तथ्यों पर आधारित अपना मत प्रकट करते, जिससे अपीलीय अधिकारी के आदेश/निर्णय के विरुद्ध अपील होने पर सम्बन्धित न्यायालय अपना निर्णय पारित करें कि अवर अधिकारी का निर्णय न्याय संगत है अथवा नहीं। किन्तु प्रस्तुत निगरानी में कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। अपीलीय अधिकारी का दायित्व बनता है कि वह सचेतन मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए निष्पक्ष अभिव्यक्ति दें। प्रार्थी निगरानीकार के विद्वान अभिभाषक द्वारा उद्धृत माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ के सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टैक्स,कोटा बनाम मैसर्स शुक्ला एड ब्रदर्स

(Civil Appeal No. Nil of 2010/S.L.P.(C)No. 16466 of 2009), date 15.4.2010) में पारित किय गये निर्णय के कुछ अंश उद्धृत किया जाना उक्त परिप्रेक्ष्य में समीचीन होगा :-

".... To subserve the purpose of justice delivery system therefore, it is essential that the Courts should record reasons for its conclusions whether disposing of the case at admission stage or after regular hearing."

"A litigant has legitimate expectation of knowing reasons for rejection of his claim/payer. It is then alone, that a party would be in a position to challenge the order on appropriate grounds. As arguments bring things hidden and obscure to the light of reasons, reasoned judgment where the law and factual matrix of the case it discussed provided lucidity and foundation for conclusions or exercise of judicial discretion by the Courts. Reason is the very life of law. When the reason of a law once ceases, the law itself generally ceases. Such is the significance of reasoning in any rule of law. Giving reasons furthers the cause of justice as well as avoids uncertainty. As a matter of fact it helps in the observance of law of precedent. Absence of reasons on the contrary essentially introduces an element of uncertainty, dissatisfaction and give entirely different dimensions to the questions of law raised before the higher appellate Courts. When reasons are announced and can be weighed, the public can have assurance that process of correction is in place and working. It is requirement of law that correction process of judgments should not only appear to be implemented but also to have been properly implemented. Reasons for an order would ensure and enhance public confidence and would provide due satisfaction to the consumer of justice under our justice dispensation system." उपरोक्त विधिक धारणा से भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है।

9. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि निगरानीधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है तथा यदि प्रकरण में निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाकर प्रतिप्रेषित किया जाता है तो न्यायिक दृष्टिकोण से प्रार्थी को सुनवाई का भी समुचित अवसर मिल सकेगा।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विवेचना-विश्लेषण सहित निर्णय पारित नहीं करने के कारण विधिसम्मत नहीं होने के कारण निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए, राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 2004 के नियम 65 की पालना करते हुए पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.02.2017 को पेश हों।

11 निर्णय सुनाया गया।

न. २०१५/१-२०१७
(नत्थूराम)
सदस्य